खुलासा - महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के जीजा ने बदली थी जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

जनज्वार, दिल्ली। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के जीजा ने जज लोया के पोस्टमार्टम में दिखाई थी विशेष दिलचस्पी, कारवां पत्रिका की नई रिपोर्ट में हुआ इसका खुलासा।

मुंबई हाईकोर्ट के जज लोया हत्याकांड का खुलासा करने वाली पत्रिका कारवां ने फिर एक बार सनसनीखेज दावा किया है। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नागपुर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मकरंद व्यावहारे ने राजनीतिक संबंधों को निभाने के लिए जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल की है।

पर चालाकी देखिए कि इस मामले के मास्टरमाइंड डॉक्टर मकरंद के हस्ताक्षर न तो जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की किसी फाइल पर हैं, न ही अदालत के किसी कागजात पर। पहली निगाह में लगता है कि मकरंद का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन जब खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि भाजपा ने अपने अध्यक्ष और सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर मामले के आरोपी अमित शाह को बचाने के लिए कहां—कहां चादर तान रखी है।

मुंबई हाईकोर्ट के जज लोया की उस समय मौत हो गयी जब वह गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे और संभव था कि वह अगली सुनवाई पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को गिरफ्तार करने के आदेश दे सकते हैं। ऐसे में पूरी भाजपा अपने अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद अमित शाह को बचाने के लिए झोंक दी गयी। ताकत इसलिए भी झोंकी कि अगर अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख मामले में नपते तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी पर आंच नहीं आती, यह असंभव था।

गौरतलब है कि गुजरात के सोहराबुद्दीन अनवर हुसैन शेख़ की 26 नवंबर 2005 को फ़र्ज़ी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। हत्या के एक चश्मदीद गवाह रहे तुलसीराम प्रजापति की भी दिसंबर 2006 में एक मुठभेड़ में मार दिए गए। उसके बाद सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी की भी हत्या हो गयी। इन सभी हत्याओं के आरोप गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह पर लगे, जिसके बाद अमित शाह की गिरफ्तारी हुई।

अमित शाह की हत्या में संलिप्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच चली। अमित शाह की इन हत्याओं में संलिप्तता का आरोप इतना सीधा था कि अदालत ने अमित शाह को राज्य–बदर कर दिया गया कि वह जांच को प्रभावित न कर सकें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर करने की और कहा कि सुनवाई के दौरान जजों का तबादला न किया जाए।

पर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष जज जे टी उत्पत का ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मई 2014 में अदालत में उपस्थित होने समन किया। शाह ने पेश होने की छूट मांगी पर जज उत्पत ने नहीं दी, जिसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रांसफर कर दिया गया।

इसके बाद ये मामला जज लोया को सौंप दिया गया, पर यहां भी अमित शाह जज लोया की अदालत में पेश नहीं हुए और एक दिसंबर 2014 को लोया की मौत नागपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद जो जज एमबी गोसावी अमित शाह की संलिप्तता की जांच के लिए आए उन्होंने आते ही एक दिन का समय गवांए बिना दिसंबर 2014 में अमित शाह को इस मामले से बरी कर दिया और वह अपने बाल—बच्चों के साथ सुख चैन से जी रहे हैं।

नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. मकरंद व्यावहारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुधीर मंगतीवार के जीजा हैं। कारवां की जांच रिपोर्ट के तथ्यों पर गौर करें तो बहुत साफ हो जाता है कि व्यावहारे ने न सिर्फ अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर जज लोया की मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने मनमुताबिक बनवाया है, बल्कि इसके लिए जिस तरह का भी हथकंडा अपनाने की जरूरत पड़ी है, उसका इस्तेमाल किया है।

नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग में न्यायाधीश बीएच लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दो महीने तक रिपोर्टर निकिता सक्सेना ने सिलसिलेवार जांच की। इस जांच के बाद निकिता ने अपनी रिपोर्ट में कई नए खुलासे किए हैं। इस खुलासे के बाद लोया हत्याकांड के संदेहों को बहुत ही प्रामाणिक तथ्य मिले हैं, जिससे साफ हो जाता है कि बहुत ही चालाकी और तैयारी के साथ जज लोया की हत्या को हर स्तर पर हॉर्ट अटैक में बदलने की सुनियोजित तैयारी की गयी है।

महत्वपूर्ण यह है कि जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर मकरंद व्यावहारे के निर्देश पर जारी की गई थी। व्यावहारे ने तय किया था कि जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन—कौन से विवरण शामिल किए जाने हैं और किन तथ्यों को शामिल नहीं करना है। बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा पोस्टमार्टम में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतों पर जांच बिठाई गई थी। डॉ. मकरंद जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी चालाकी से फेरबदल करवाए थे, वह जज लोया के किसी भी मेडिकल दस्तावेज में और अदालत में तक अपने नाम को सामने नहीं आने देने में अब तक सफल हो रहा था। जज लोया मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गड़बड़ी में जितनी बड़ी भूमिका डॉ. व्यावहारे की रही है, वह अब तक मीडिया में सामने नहीं आ पाई है।

सरकारी आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक जज लोया का पोस्टमार्टम डॉ. एनके तुमराम ने किया था, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग में लेक्चरर थे। जबकि सच्चाई यह है कि पोस्टमार्टम डॉ. मकरंद व्यावहारे के निर्देशों पर किया गया था, जो तब वहीं प्रोफेसर थे और अब इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर में फोरेंसिक विभाग के प्रमुख हैं। व्यवहारे महाराष्ट्र की पावरफुल मानी जाने वाली चिकित्सा परिषद के सदस्य भी हैं जो कि राज्य के सभी चिकित्सकों के लिए पर्यवेक्षी निकाय है।

डॉ. व्यवहारे संस्थान और मेडिकल कॉलेज में राजनीतिक संबंधों के चलते कोई भी काम करवाने वाले शख्स के बतौर जाने जाते थे। अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ लेकर ही वे एक लेक्चरर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट समेत अन्य पावरफुल जगहों पर पहुंच बनाने में सफल रहे हैं। व्यावहारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार के जीजा हैं, जो कि फड़नवीस की कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखते हैं।

पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे कर्मचारियों ने रिपोर्टर से हुई बातचीत में बताया कि डॉक्टर व्यावहारे पूरे पोस्टमार्टम के दौरान खुद खड़े रहे। डॉक्टर व्यावहारे उस समय बुरी तरह भड़क उठे जब एक जूनियर डॉक्टर ने जज लोया के सिर और पीठ पर लगी चोट को लेकर सवाल किया। कर्मचारियों के मुताबिक डॉक्टर व्यावहारे किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी उन तथ्यों का जिक्र हो जो मौके पर दिखाई दे रहे थे।

डॉक्टरी रिपोर्टों के मुताबिक जज लोया की मौत हॉर्ट अटैक से हुई है। लेकिन इस जांच रिपोर्ट से साफ है कि जज लोया की मौत का सच जान—बूझकर छुपाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री के जीजा ने भाजपा हाईकमान के इशारे पर एक साजिशकर्ता की भूमिका निभाई है।

इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के इलाके में एक दु:खद हादसा : दस मौतों को सरकार पी गयी

इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के इलाके में एक दु:खद हादसा हुआ एक बहुमंजिला होटल की इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई ओर अभी भी कुछ लोग लापता हैं लेकिन कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस घटना की रिपोर्टिंग करते हुए इस घटना को कार की टक्कर से हुई दुर्घटना का रूप दे दिया अनेक न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ साइट पर यही हेडलाइन बनाई , एनडीटीवी ने भी.......

क्या किसी कार के किसी इमारत के पिलर से टकरा जाने पर इमारत गिर सकती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्कोडा कार की टक्कर से होटल के पिलर को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही थी वो बन्दा अब सामने आया है और बोल रहा है कि मैं तो गाड़ी पार्क कर के चला गया था

प्रश्न यह उठता है कि दस लोग मारे जाते हैं कई घायल होते हैं तो मीडिया इस घटना को इस तरह से क्यो प्रस्तुत करने में इंटरस्टेड दिखाई देता है जिससे लोगो का ध्यान सिर्फ तात्कालिक कारण पर जाए, कारण इंदौर में हुई पिछली दुर्घटना में छिपा है।

जब डीपीएस स्कूल वाला बस हादसा हुआ तो जैसी घटना हुई उसे वैसा ही पेश किया गया और उस घटना में प्रशासनिक लापरवाही की बात बहुत बड़ा मुद्दा बन गयी, ओर मुख्यमंत्री तक को इस घटना पर स्पष्टीकरण देना पड़ा, इसलिए इस बार इस घटना में विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि प्रशासनिक लापरवाही जैसी बात दबा दी जाए और 10 लोगो की मृत्यु को एक दुर्घटना का रूप दिया जा सके। जिस रूस-होटल की इमारत ढही है बताया जा रहा है कि वह 80 साल पुरानी थी इस खतरनाक इमारत को नगर निगम को सालो पहले ही तोड़ देना चाहिए था, ओर इसकी लोकेशन इतने व्यस्ततम इलाके में थी कि हर अधिकारी को इसकी जर्जर स्थिति दिखती ही होगी , होटल मालिक ने इसे तोड़ने के बजाय 2 और मंजिल बना दी, 8 दिन पहले ही इसकी 1 छत गिरी थी यह इमारत इतनी बुरी स्थिति में थी कि जब भी तेज रफ्तार से बस निकलती यह थरथराने लगती थी। होटल के बेसमेंट में भी पानी भरा था, जिससे उसकी नींव भी लगातार कमजोर हो रही थी लेकिन शिवराज सरकार के अधिकारियों को तो बस मोटा माल कमाने से फुर्सत नही मिलती वो कहा इसे देखते, ...तो इंदौर के इतिहास में घटी सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक की घटना को मीडिया द्वारा मैनेज कर लिया गया, आखिर छह महीने बाद चुनाव है सही रिपोर्टिंग होगी तो पब्लिक भड़क नही जाएगी ?

काला धंधा गोरे लोग........ भाजपा सरकारों ने कोयला अदानी के पास गिरवी रखा

(म. मो. विशेष) लीजिए एक और घोटाला सामने आया है और वह घोटाला भी छोटा मोटा नही है पूरे 125 करोड़ का घोटाला है। छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथों बेच दिया गया है। ढाई हजार मिलियन टन क्षमता वाले छह कोल ब्लॉक को नीलाम न करके तीन भाजपा शासित राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियों को आवंटित कर दिया गया है।

कहने को कोल ब्लॉक्स कागजों में तो सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियों के हैं, लेकिन उनकी असली संपत्ति एक निजी कंपनी अडानी को माइन डेवलप एंड ऑपरेट (एमडीओ) नियुक्त करके सौंप दी गई है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में कुल 88 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला निकालने का काम या तो अडानी के पास पहुंच चुका है या फिर इसकी तैयारी अंतिम चरणों में है।

उदाहरण के लिए आप देखिए कि पतुरिया गिधमुड़ी कोल ब्लॉक भैया थान पॉवर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया है। यह पॉवर प्रोजेक्ट इंडिया बुल्स के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार को बनाना था लेकिन यह परियोजना शुरु ही नहीं हो सकी और इंडिया बुल्स वापस चली गई। लेकिन इस कोल ब्लॉक से कोयला निकालने की तैयारी हो रही है। जब परियोजना ही नहीं है तो फिर कोयला क्यों निकाला जाएगा ? किसके लिए निकाला जाएगा ? छत्तीसगढ़ सरकार कोयला व्यापारी तो है नहीं तो फिर यह मोदीजी के इशारे पर अडानी को उपकृत करने के अलावा और क्या है ?

ओर इन्हीं आधार पर अडानी कह रहे हैं कि कि अगले दशक में उनका कोयला उत्पादन 150 मिलियन टन हो जाएगा।

जिन खदानों से जुड़े हुए कोल ब्लॉक में हिंडाल्को 3500 रु प्रति टन कोयला निकाल रहीं हैं वही अडानी को मात्र 100 रु प्रति टन में ठेका दिया गया है कहने को तो यह आरोप कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश पटेल लगा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र स्त्रोतों से भी इसकी पुष्टि होती है कि किस तरह से सरकारी अधिसूचनाओं में मनमाने परिवर्तन करा कर अडानी किस तरह से कोयले को खुले बाजार में बेच कर अरबो खरबो के मुनाफे का खेल खेलने को तैयार बैठे।

दिन रात 2 जी स्कैम ,राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कोल ब्लॉक में भ्रष्टाचार आदि घोटाले की राग रागनियां को गा कर जो लोग सत्ता में आये थे वो ही आज नया कोयला घोटाला करने से बाज नही आ रहे।

- प्रदीप कासनी

एसआरएस ग्रुप वाले गिरफ्तार - नीमका जेल में आयी बहार

फरीदाबाद (म. मो.) एसआरएस एस ग्रुप के मालिकान और डायरेक्टरों सहित पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नीमका जेल भेजे जाने से वहां के जेल अधीक्षक अनिल कुमार की मौज आ गयी. वह काफी लम्बे समय से किसी मोटी मुर्गी के आने का इन्तजार कर रहा था।

कैदियों के राशन को हड़पने, बीड़ी के बंडल ब्लैक में बेचने, कैंटीन की खाने पीने की वस्तुएं दुगने तिगुने दाम पर बेच कर जितना मुनाफा साल भर में नहीं होता उससे कहीं अधिक उसकी आय तो एसआरएस वालों से एक दिन में ही हो जायेगी।

इस संवाददाता का व्यक्तिगत अनुभव है कि इस तरह की मोटी आसामी जब भी जेल में आती हैं टी जेल अधीक्षक अनिल उन्हें पहले दिन ही इतना भयभीत कर देता है कि एक झटके में करोड़ दो करोड़ का प्रबंध हो जाता है. सन 2012 में इस संवाददाता ने अपने सामने ऐसी ही एक आसामी से अनिल को इसी जेल में 50 लाख लेते देखा है।

कल्पना कीजिये, इतनी बड़ी रकम लेकर एक आदमी बाकायदा जेल की ड्योढी में प्रवेश करता है. नियमानुसार होने वाली तलाशी में नोटों की गड्डियां सारे जेल कर्मचारी देखने के बाद अनिल के पास भेज देते हैं जो इस रकम को रख लेता है. रिश्वत लेने का इतना बेजोड़ ढंग सुनने में नहीं आया था।

अब काफी अरसे बाद एसआरएस मालिकान के रूप में जेलर अनिल को कम से कम पांच करोड़ की आसामियां हाथ लगी हैं. भीतर की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि अब अनिल काफी सतर्क होकर पैसे पकड़ता है। हो सकता है कि इतनी बड़ी पेमेंट वह अपने किसी दल्ले की मार्फत पकड़े।

विधायक पति की हार ने खुश कर दी बार

फरीदाबाद (म. मो.) छ: अप्रैल को हुए स्थानीय बार चुनाव में बॉबी रावत की जीत ने वकीलों को इतना खुश नहीं किये बढ़खल विधायक सीमा त्रिखा के पति अश्वनी त्रिखा की हार ने। करीब डेढ़ सौ मत के अंतर से जीत कर बार प्रधान बने बॉबी रावत के बारे में वकीलों का कहना है कि उन के पास तो कोई लिफाफा यानी केस ही नहीं, इसलिए वे तो क्या ही सौदेबाजी करेंगे. हाँ, त्रिखा के पास कुछ काम-धाम है।

उनकी पत्नी के विधायक बनने के बाद वे बेशक अदालतों में कम ही दिखाई देते हैं, फिर भी किसी न किसी न्यायिक या प्रशासनिक काम के लिए लोग उनके पास अच्छी खासी संख्या में आते रहते हैं। बार प्रधान होने पर उनकी मारक क्षमता जाहिर है डबल हो जानी थी, जो हार से रह गयी।

उनकी हार के पीछे भाजपा का वह ग्रुप भी था जो सीमा त्रिखा के विरुद्ध रहा है. इसके अलावा गत विधान सभा चुनाव में सीमा से हारे पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने तो खुलकर अश्वनी की मुखालफत की थी. इस बाबत मजदूर मोर्चा ने पिछले अंक में विस्तृत जानकारी दी थी।